

अमेरिका के विदेश सचिव रूबियो ने ढूँढ कर एस. जयशंकर से मुलाकात की और बहुत मीठी-मीठी बातें कीं

रूबियो के इस प्रयास से भारत का विदेश मंत्रालय अचंभित, पर खुश भी है

- रूबियो ने अपनी मीठी बातों से ट्रंप की तल्खियों को बेलेंस करने का प्रयास किया।
- भारत में यह धारणा जोर पकड़ती जा रही थी कि ट्रंप भारत से संबंधों को तत्कालिक आर्थिक लाभ के चश्मे से देखते हैं, न कि दीर्घकालीन स्थाई आर्थिक लाभ दृष्टि से।
- कुछ समय पूर्व तक 65 प्रतिशत भारतीय जनता अमेरिका से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना चाहती थी जो 2023 में 50 प्रतिशत रह गई।
- भारत का विदेश मंत्रालय रूबियो के प्रयास से इसलिए भी प्रसन्न है, क्योंकि इस प्रयास से यह स्थापित हो गया कि वॉशिंगटन से भारत की मित्रता ऑटोमैटिक नहीं है, बल्कि यह रिश्ता भारत के आर्थिक हित व स्वायत्तता के आदर पर ही स्थापित हो सकता है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। कुछ दिन पहले 48 वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान कुआलालंपुर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से हुई मुलाकात ने कूटनीतिक हलकों से कहीं आगे तक ध्यान खींचा है। यह भेंट भले ही एक शिष्टाचार भेंट प्रतीत होती है, लेकिन इसके पीछे यह गहरा संदेश छिपा है कि डॉनल्ड ट्रंप की तीखी बयानबाजी और टैरिफ की धमकियों के बावजूद, वॉशिंगटन नई दिल्ली को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में महत्व देता है। भारत के लिए, यह मुलाकात इरादों की परीक्षा थी: क्या ट्रंप का अमेरिका अब भी एक विश्वसनीय मित्र है, या फिर हितों को तोलने वाला लेन-देन आधारित साझेदार?

एक प्रमुख रिपब्लिकन नेता और ट्रंप के सबसे करीबी सीनेट सहयोगियों में से एक, रूबियो, चीन के खिलाफ सख्त रुख और इण्डो-पैसिफिक साझेदारी को मजबूत करने के समर्थक रहे हैं। जयशंकर के साथ उनकी यह भेंट, शांत कूटनीति, ट्रंप की आक्रामक शैली और संस्थागत स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। भारत के लिए द्विदलीय समर्थन को रेखांकित करके, रूबियो का उद्देश्य था, इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका द्वारा भारतीय

इस्पात और दवा कंपनियों पर नए टैरिफ लगाए जाने के बाद नई दिल्ली के नीतिगत हलकों में उभरी आशंकाओं को शांत करना।

समय महत्वपूर्ण था। भारत में जनता की भावना, जो कभी अमेरिका के प्रति अत्यधिक सकारात्मक थी, अब फिसलने लगी है। सर्वेक्षणों के अनुसार, 2023 में जहाँ 65 प्रतिशत भारतीय अमेरिका के प्रति सकारात्मक रुख रखते थे, वहीं 2025 के मध्य में यह आंकड़ा बमूशिकल 50 प्रतिशत रह गया और यह धारणा बढ़ती जा रही है कि वॉशिंगटन का “अमेरिका फ्रस्ट” व्यापार एजेंडा

भारत जैसे साझेदारों को दरकिनार कर रहा है। व्यापक चिंता यह है कि ट्रम्प 2.0 में अमेरिका अपने सहयोगियों को दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास के बजाय, मुख्य रूप से अल्पकालिक आर्थिक लाभ के नज़रिए से देख रहा है।

इस प्रकार, रूबियो का हस्तक्षेप इसलिए भी अहम था, क्योंकि उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी के स्तंभों-प्रौद्योगिकी सहयोग, रक्षा सहयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों को दोहराया। उन्होंने कथित तौर पर सेमीकंडक्टर निवेश के विस्तार, संयुक्त रक्षा उत्पादन और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर

चर्चा की, जो ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग में चीन के विकल्प के रूप में उभरने की भारत की महत्वाकांक्षा के अनुरूप है। नई दिल्ली के लिए, ये प्रतिबद्धताएँ मायने रखती हैं: ये संकेत देती हैं कि अमेरिका के साथ संबंध सिर्फ एक बेलेंस-शीट गणना से कहीं बढ़कर हैं।

फिर भी, ये प्रतीकात्मकता इस विषमता को छिपा नहीं सकती। हालाँकि अमेरिका अपनी हिंद-प्रशांत रणनीति में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, फिर भी उसने व्यापार बाधाओं, डेटा स्थानीयकरण और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्वदेशी सर्वेक्षण पोत नौसेना में शामिल होगा

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। देश में ही निर्मित सर्वेक्षण पोत इक्षक को अगले महीने कोच्चि नौसैनिक बेस में नौसेना के बेड़े में शामिल किया जायेगा। नौसेना के प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि इस पोत को 6 नवम्बर को नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में नौसेना में शामिल किया जायेगा। इक्षक नौसेना में शामिल किये जाने वाला अपनी श्रेणी का तीसरा पोत है और यह उन्नत, अत्याधुनिक प्लेटफार्मों के

- कोच्चि नौसेना बेस पर नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में 6 नवम्बर को ‘इक्षक’ को बेड़े में शामिल किया जायेगा।

निर्माण के प्रति नौसेना की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। साथ ही इससे क्षमता संवर्धन और आत्मनिर्भरता की गति को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी जल सर्वेक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता में एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड, कोलकाता द्वारा निर्मित पोत इक्षक में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। यह पोत जीआरएसई और भारतीय एमएसएमई के बीच सफल सहयोग का प्रमाण है, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना और शक्ति को गर्व से दर्शाता है।

जल सर्वेक्षण कार्यों की प्राथमिक भूमिका के अलावा इसे दोहरी भूमिका (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘अगर जनरल लड़ाई छोड़ भागे तो सेना कब तक टिकी रह सकती है?’

प्रशांत किशोर की स्वयं चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद उनकी पार्टी साइड लाइन्ड सी हो गई है बिहार चुनावों में

- शायद यह भांपते हुए, प्रशांत किशोर ने यह टिप्पणी की है कि चुनाव के बाद या तो वे अर्थ पे होंगे या फिर फर्श पर।
- कांग्रेस भी कुछ नाखुश सी लगती है, तभी पटना में मंगलवार को तेजस्वी यादव द्वारा जारी होने वाले महागठबंधन के घोषणा पत्र के समारोह में न तो राहुल गांधी होंगे और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे।
- भाजपा भी कुछ मायूस सी है कि अब तक प्रधानमंत्री के पूरे शासनकाल में पार्टी अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकी।
- भाजपा को आशा है कि इस बार उसकी इस आकांक्षा की पूर्ति होगी।

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। भारी उतार चढ़ाव का सामना कर रहे बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है और चुनावों में सीधे मुकाबले के आसार प्रबल हो रहे हैं। तेजी से हो रही उथल-पुथल एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर की ओर बढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि प्रशांत किशोर का बहुचर्चित तीसरा पहिया धीरे-धीरे हाथियों पर जा रहा है।

माना जा रहा है कि जिस दिन प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव न लड़ने की घोषणा की, उसी दिन उनका चुनावी दांव उल्टा पड़ गया। इसके बाद यह आरोप लगने लगे कि अगर जनरल मैदान छोड़ दें, तो क्या सेना उनके पीछे आ सकती है? प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके थे कि या तो वह पहले होंगे या आखिरी। अर्थ पे या फ़र्श पे।

महागठबंधन का चुनावी घोषणापत्र कल जारी होगा, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तेजस्वी यादव के साथ न तो राहुल गांधी और न ही मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद होंगे। राहुल गांधी के खास माने जाने वाले के.सी.

वेणुगोपाल पटना में हैं और उनके पार्टी का प्रतिनिधित्व करने की संभावना है। राहुल गांधी 28 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ बिहार में तीन जनसभाएँ करेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी के साथ राहुल की सभा के लिए कुछ और दिन निर्धारित किए गए हैं। चुनाव के बाद अगर महागठबंधन सत्ता में आता है, तो कांग्रेस का एक उपमुख्यमंत्री होगा, लेकिन इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। वे सहनी

को उपमुख्यमंत्री बनाने पर इसलिए सहमत हुए क्योंकि वे कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार थे। सहनी की वीआईपी पार्टी का कई इलाकों में अच्छा-खासा प्रभाव है और उनके गठबंधन में शामिल होने से महागठबंधन को फायदा होने की संभावना है।

भाजपा ने मुख्यमंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों और अन्य लोगों को बिहार में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आखिर बिहार चुनाव प्रचार से क्यों दूर हैं राहुल

राहुल ने आखिरी बार एक सितम्बर को बिहार में सभा की थी, उसके बाद से वे बिहार नहीं गए हैं

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। राहुल गांधी को बिहार में आखिरी बार 1 सितम्बर को देखा गया था, जब उन्होंने अपनी ‘चोटर अधिकार यात्रा’ की समापन रैली को संबोधित किया था। इसलिए सवाल यह उठता है कि आखिर क्या कारण है कि वे चुनावी राज्य बिहार में इतने लंबे समय से अनुपस्थित हैं? क्या उनका अनुपस्थित रहना महागठबंधन की इस रणनीति का हिस्सा है, कि राहुल बनाम मोदी का मुद्दा मुख्य रूप से सामने न आए? क्या इसका कारण यह है कि राहुल राज्य पार्टी नेतृत्व से नाखुश हैं, क्योंकि वह आरजेडी के साथ सीटों के बंटवारे पर दृढ़ता नहीं दिखा सका? या फिर क्या ऐसा इसलिए है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किए जाने के बाद, वह नहीं चाहते कि उन्हें आरजेडी नेता के सामने दूसरे नम्बर के

- यहाँ तक कि महागठबंधन का घोषणा पत्र मंगलवार को जारी किया जा रहा है, पर, उसमें भी राहुल उपस्थित नहीं हो रहे हैं।
- चर्चा है कि राहुल एक तो प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टी लालू यादव से सीटों के लिए सही तरीके से सौदेबाजी नहीं कर पाई।
- इसके अलावा तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किए जाने के कारण, राहुल बिहार में दूसरे दर्जे की भूमिका निभाना नहीं चाहते हैं।

नेता के रूप में देखा जाए?

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई अन्य नेता जल्द ही बिहार का दौरा करेंगे और 6 नवम्बर को प्रचार अभियान के समापन से कुछ दिन पहले एक जोरदार प्रचार करेंगे। संकेत मिल रहे हैं कि राहुल 2 नवम्बर को बिहार पहुंचेंगे और पहले चरण में खगाड़िया

और सीमांचल क्षेत्र के अन्य स्थानों पर रैलियों को संबोधित करेंगे। हालाँकि, सवाल यह भी है कि कांग्रेस के लिए यह बहुत देर से की गई कोशिश तो साबित नहीं होगी?

शीर्ष भाजपा नेताओं में नरेन्द्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ पहले ही प्रचार में जुट चुके हैं, और यहाँ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रधानमंत्री ने छठ पूजा की शुभकामनायें दी

नयी दिल्ली, 27 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों को छठ पूजा के पहले अर्घ्य के मौके पर शुभकामनाएं दीं। मोदी ने इस अवसर पर अपने एक्स पोस्ट पर कविता पोडवाल द्वारा

- उन्होंने कविता पोडवाल का छठी मैया का भक्ति गीत एक्स पोस्ट पर साझा किया।

गाया हुआ छठी मैया को समर्पित भक्ति गीत भी साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा, “देश भर के अपने परिवारजनों को महापर्व छठ के संख्या अर्घ्य की अनंत शुभकामनाएं।

इस पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने की हमारी परंपरा बहुत विशिष्ट है।

सूर्यदेव की कृपा से सबका कल्याण हो, सबको जीवन में सुख-संपदा और सफलता की प्राप्ति हो, यही कामना है। जय छठी मइया!”

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं। इस समझौते के तहत, भारत से अमेरिका जाने वाले निर्यात पर लगाए गए “रैसिप्रोकल टैरिफ” हटाए जा सकते हैं।

रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर लगाए गए भेदभावपूर्ण शुल्क को भी इस दौर की व्यापार वार्ता में शामिल किया गया है और संभावना है कि इसे भी वापस लिया जा सकता है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर एक विशेष दंडात्मक शुल्क लगाया था। उन्होंने रूस के साथ ऐसे तेल व्यापार में लेन-देन की सुविधा प्रदान करने वाले बैंकों और वित्तीय कंपनियों पर भी अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इन प्रतिबंधों के बाद, अधिकांश

- भारत ने भी मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिकी कंपनियों से तेल खरीद शुरू कर दी, जिससे अमेरिका ने भारत पर लगाये रैसिप्रोकल टैरिफ हटाने का इरादा दिखाया।
- इस घटनाक्रम से भारत-अमेरिका ट्रेड, लाईन पर आना शुरू हो गया है।
- भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कलकत्ता में पत्रकारों से बात करते हुए संकेत दिए।

बैंकों ने रूसी तेल कंपनियों के साथ किसी भी तरह के लेन-देन से परहेज करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने अपने ताजा आदेशों के तहत, रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों, रोसेनेफ्ट और लुकोइल पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगा दिए हैं।

कई भारतीय कंपनियों कथित तौर पर अब मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिकी और अमेरिकी कंपनियों से तेल खरीदने पर विचार कर रही हैं, जो रूसी तेल कंपनियों के साथ अपने खरीद समझौते

समाप्त कर रही हैं। एक बार जब वे कंपनियाँ रूसी तेल खरीद से दूर हो जाएँगी, तो विशेष दंडात्मक शुल्क हटाना जा सकता है।

यह घटनाक्रम अमेरिका के साथ एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंध, नए सिरे से तय किये जाएँ, जैसा कि उसने अन्य देशों के साथ किये थे।

भारत ने व्यापार वार्ता शुरू तो की

थी, लेकिन उसने अमेरिकी माँगों के आगे घुटने नहीं टेके और अपने व्यापारिक हितों पर डटा रहा। इसके परिणामस्वरूप, अमेरिकी राष्ट्रपति ने मनमाने ढंग से “भारतीय निर्यात पर रैसिप्रोकल टैरिफ” लगा दिए। अब तक दोनों देशों के बीच पाँच दौर की वार्ताएँ हो चुकी हैं, ताकि मतभेद दूर कर एक “फ्रेमवर्क एग्रीमेंट” (रूपरेखा समझौता) तैयार किया जा सके। लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हो पाया, क्योंकि दोनों देशों के विचार कई मुद्दों पर अलग-अलग थे, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में बाजार तक पहुँच को लेकर।

जहाँ अमेरिका ने अपने कृषि उत्पादों के लिए अधिक पहुँच की माँग की थी, वहीं भारत ने भारतीय किसानों, खासकर छोटे किसानों, की चिंता के कारण अमेरिकी अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा, दवाओं और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राम मंदिर परिसर के सभी 15 मंदिरों का निर्माण पूरा

अयोध्या, 27 अक्टूबर। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य मंदिर समेत परकोटे के छह मंदिरों (शिव, गणेश, हनुमान, सूर्य, मां भगवती, मां अन्नपूर्णा और शेषावतार मंदिर) का निर्माण पूरा हो गया है। साथ ही, इन सभी पर

■ श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह जानकारी दी व कहा कि ध्वजारोहण समारोह के बाद श्रद्धालु सभी मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे।

ध्वजदंड और कलश भी स्थापित कर दिये गये हैं। परिसर के सभी 15 मंदिर अब पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। यह जानकारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

यदि देश भक्ति का मतलब व्यापक मानव मात्र का हित चिंतन नहीं है तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। –महात्मा गाँधी

नोट के बदले वोट, लोकतंत्र पर चोट

लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्व नागरिक– मतदाता का होता है। उसी के वोट के आधार पर यह तय होता है कि 5 वर्ष के लिए राज्य अथवा केंद्र में किस दल को बहुमत मिलेगा और किसकी सरकार बनेगी? चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपादित करने के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 बनाया गया। इस कानून में चुनाव की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें उम्मीदवारों के लिए व्यय की अधिकतम सीमा लोकसभा के लिए 95 लाख तथा विधानसभा के लिए 40 लाख निर्धारित की गई है। इस कानून की अवहेलना होने पर किसी भी जीते हुए उम्मीदवार का चुनाव न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

कानून के अतिरिक्त, चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देने या प्रताड़ित करने के प्रकरण कुछ समय पहले तक बहुत अधिक सामने आते थे। कुछ दशक पहले, मतदान के एक दिन पहले शराब, सामग्री और नकद बांटना आम बात थी। ऐसा राजनीतिक दलों द्वारा इस सोच के साथ किया जाता था कि इस प्रकार सामग्री वितरण से मतदाता उनके पक्ष में मतदान करेंगे और वे सत्ता में आएंगे। अनेक बार ऐसा हो भी जाता था, क्योंकि भारतीय मतदाता अधिकांशतया अशिक्षित और निर्धन थे। तब मीडिया भी इतना अधिक जागरूक नहीं था। यह उल्लेखनीय है कि चुनाव खर्च की निर्धारित सीमा में, संबंधित उम्मीदवारों के दलों द्वारा किया गया खर्च सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसीलिए चुनाव से पूर्व किया गया बड़ा खर्चा वह होता है जो किसी उम्मीदवार के खाते में तो नहीं जाता, किंतु मतदाताओं को रिझाने के लिए होता है। रैलियों, सभाओं के साथ ही आवश्यकता से अधिक वाहनों का प्रयोग, मतदाताओं को कई प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास, दलों की इसी धनराशि से होता आया है।

कानून के साथ ही, चुनाव प्रचार के दौरान शुचिता और गरिमा बनी रहे ,इसके लिए आदर्श चुनाव संहिता या “मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट” बनाया गया। इसका उद्देश्य भाषा की मर्यादा बनाए रखना तथा सत्ता के दुरुपयोग को रोकना था। इस अवधि में सरकार के मंत्री, सांसदों एवं विधायकों पर सरकारी सुविधाओं का उपयोग करने पर भी प्रतिबंध लग जाता है। चुनावों की घोषणा होने के बाद सरकार कोई नीतिगत निर्णय भी नहीं ले सकती है।

चुनाव आयोग पर हाल ही के दिनों में यह आरोप लगाते रहे हैं कि वह सत्ता धारी दल पर आदर्श चुनाव संहिता लागू करने में विपक्षी दलों की तुलना में कम सख्ती दिखाता है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को अनेक शिकायतें चुनाव अधिकारियों को प्राप्त होती हैं जिन पर केवल नोटिस देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। सामान्यतः ये शिकायतें चुनाव होने के बाद फाइलों में दबी रह जाती हैं। संभव है, इसी कारण, राजनीतिक दल एवं उनके नेता आदर्श आचार संहिता को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। इस हेतु कोई कानूनी कारवाई भी नहीं की जा सकती क्योंकि आचार संहिता को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।

हाल ही के दिनों में, मतदाताओं को प्रलोभन देने का नया तरीका सामने आया है, जो एक प्रकार से मतदाताओं को खरीदने जैसा ही है। इस प्रकार का कार्य वे सभी दल करने में लगे हैं जो सत्ता में हैं। इसके कुछ उदाहरण देने उपयुक्त होंगे।

गत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले लगभग सभी चुनावी सर्वेक्षण यह बता रहे थे कि महा विकास अगाड़ी, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव) और राष्ट्रवादी कांठोस पार्टी (शरद पवार) सम्मिलित थे, को बहुमत मिलेगा।

चुनाव से कुछ दिनों पूर्व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ‘लाडकी बहिन’ योजना की घोषणा कर दी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक निर्वाश्रित महिला के खाते में प्रतिमाह 1500 रुपए जमा करा दिए गए। इस कारण, चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 1500 रुपए जमा हो गए। क्योंकि योजना की घोषणा चुनाव की तिथियां घोषित होने से पूर्व की गई थी, चुनाव आयोग का कोई अधिकार इस रोकने का नहीं था। यह पैसा सरकारी

बिहार का चुनाव परिणाम यह तय करेगा कि बिहार का मतदाता क्या अपने खाते में एक बार सीधी धनराशि प्राप्त करके संतुष्ट हो जाएगा और इसके आधार पक्ष में मतदान करेगा? प्रशांत किशोर की जन सुराज को छोड़कर शेष सभी दल केवल मतदाताओं को नोट देकर वोट लेने की बात कर रहे हैं । इस प्रक्रिया में हम यह भूल गए कि नोट बांटकर वोट बटोरने का काम लोकतंत्र पर चोट करने वाला है।

खजाने से दिया गया जो सारा जनाता का पैसा था। इसका असर यह हुआ कि जब चुनाव के परिणाम आए तो सभी सर्वेक्षणों के निपरीत, भाजपा-शिवसेना (शिंदे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजीत पवार) के गठबंधन महा युति को अच्छी खासी जीत मिली एवं उन्होंने दुबारा सरकार बनाई। इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस योजना के कारण महाराष्ट्र सरकार की वित्तीय स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सत्ताधारी दल ने जनता के पैसे से प्रलोभन देकर चुनाव अपने पक्ष में कर लिया । सब जानते हैं कि सरकार का धन जनता से ही तो वसूल किया जाता है। इसे मनमाने ढंग से खर्च करना और चुनाव से ठीक पहले किसी वर्ग को ‘रिश्वत’ देकर अपने पक्ष में करना आदर्श



गोपेन्द्रनाथ भट्ट

भारत के विज्ञापन जगत में शब्दों का अद्भुत चितेरा माने जाने वाले और जयपुर के बेजोड़ नगीनों में से एक पियूष पांडे अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे स्वयं पंचतत्व में विलीन होकर दिवंगत पाण्डे उपनाम से ईश्वर के स्लॉगन बन गए। पियूष पांडे की बहन विख्यात गायिका ईला अरुण के अनुसार वे सॉस से जुड़ी बीमारी से पीड़ित थे। पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित दिवंगत पाण्डे ने सात दशकों की अपनी जीवन यात्रा में दिल को छूने वाले कई अनूठे ग़िफ्ट और श्रव्य दृश्य विज्ञापन और स्लॉगन बनाये। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में अबकी बार मोदी सरकार चुनावी स्लॉगन भी बनाया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उनके निघन पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि वचों तक हमरों बीच हुई बातचीत को मैं हमेशा सहेज कर रखूंगा।

जॉन क्या दिख जाए के लॉचिंग के दौरान मेरी उनसे नई दिल्ली के बीकानेर हाऊस में पहली बार मुलाकात हुई थी। उनकी एक बहन रमा पांडे चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में हमारी पड़ोसी थी। इस सन्दर्भ से उनसे हुए परिचय के दौरान मैंने उनकी रचनात्मक दृष्टि पर खुल कर

बातचीत की थी। तब उन्होंने बहुत ही आत्मीयता से कहा था कि ईश्वर ने हम सभी को अपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए धरती पर भेजा है और एक दिन ईश्वर में ही विलीन हो कर हम भी एक स्लॉगन बन जाएँ। उनके ये शब्द आज मेरे कानों में गूँज कर मुझे भावुक कर रहे हैं। जानें क्या दिख जाए राजस्थान पर्यटन का प्रसिद्ध विज्ञापन स्लोगन था, जिसे पियूष पांडे ने वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री कार्यकाल (2004–2008) के दौरान तैयार किया था।यह स्लोगन सिर्फ एक पर्यटन नाम नहीं था बल्कि पियूष पाण्डे का राजस्थान की आत्मा और अनदेखे सौंदर्य को दर्शाने वाली एक रचनात्मक दृष्टि थी। उस समय राज्य सरकार ने प्रदेश के पर्यटन को नई पहचान देने के लिए एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया था। इसके लिए जिस विज्ञापन एजेंसी ओगिल्वी एंड माथर (Ogilvy & Mather) को विज्ञापन बनाने की जिम्मेदारी दी थी। उसके क्रिएटिव हेड पियूष पांडे ही थे। इस अभियान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और उन्हें इंडियन आइकॉन ऑफ एडवरटाइजिंग जैसे कई पुरस्कार भी मिले।

राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर में जन्में और नौ भाई बहनों के मध्य पले और बड़े हुए पूर्व रणजी क्रिकेटर पियूष पांडे कहते थे कि राजस्थान इतना विविधताओं से भरपूर है कि यहाँ हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। इसलिए जानें क्या दिख जाए! स्लॉगन बनाते समय हमने सोचा कि क्यों न लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया जाए कि राजस्थान यात्रा के दौरान वहाँ न जानें क्या दिख जाए! उनका माना था कि विज्ञापन सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि अनुभव की प्रेरणा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने राजस्थान को देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह के रूप में प्रस्तुत किया तथा कहा कि

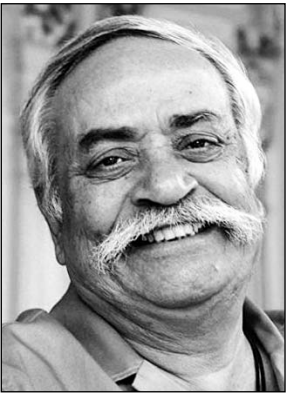
जानें क्या दिख जाए केवल एक स्लोगन नहीं बल्कि यह राजस्थान की आत्मा का गीत और आईना है, जिसे मैंने शब्दों में पिरोया है। उनकी यह रचना आज भी भारतीय पर्यटन अभियानों का एक क्लासिक उदाहरण मानी जाती है जहाँ विज्ञापन कला बन गया और शब्द भावना। भारत में पोलियो-अभियान के सघन प्रचार के लिए दो बूंद जिंदगी के जैसे स्लॉगन बनाने में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। भारत सरकार के अतुल्य भारत (Incredible India) अभियान से लेकर राजस्थान के जानें क्या दिख जाए तक पियूष पांडे ने भारत की सांस्कृतिक आत्मा को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित कर उसे एक नई पहचान दी।

वर्ष 1982 में, 27 वर्ष की आयु में, पियूष पांडे ने भारतीय विज्ञापन कंपनी ओगिल्वी एंड माथर इंडिया (Ogilvy & Mather India) में क्लाइट–सर्विसिंग एक्जीक्यूटिव के रूप में नौकरी प्रारंभ की। विज्ञापन–उद्योग में कदम रखने से पहले उन्होंने कोलकाता में चाय चखने (tea taster) जैसी नौकरियाँ भी की थीं, जहाँ उन्हें जीवन की विविध अनुभव प्राप्त हुए।

विज्ञापन–उद्योग की शुरुआत में यहाँ उनकी उम्मीदें बहुत कम थीं लेकिन उन्होंने हार न मानी और अपनी मेहनत से आगे बढ़े। उनका पहला प्रयास सनलाइट डिजैट के लिए एक प्रिंट विज्ञापन था, जिसे लिखकर उन्होंने विज्ञापन–क्षेत्र में कदम रखा। पियूष पांडे ने अपनी क्रिएटिव विचार–शैली और अद्वितीय दृष्टिकोण से भारतीय विज्ञापन–उद्योग में एक नया आयाम स्थापित किया। उन्होंने अनेक प्रतिष्ठित ब्रांड्स के लिए यादगार ऑडियो विजुअल विज्ञापन अभियान तैयार किए। भीमसेन जोशी द्वारा गाये गए कालजयी गीत फिर मिले सुर मेरा

तुम्हारा के बोल भी पियूष पाण्डे ने ही लिखें थे। उनके अन्य विज्ञापन अभियान जैसे फ़ेबिकोल के लिए।पीडो नही, जोड़ो टैगलाइन विशिष्ट दृश्य–कला से भरें थे। उन्होंने केडबरी डेयरी मिल्क के लिए कुछ खास हैं जैसे मिठास भरें लोकप्रिय स्लोगन बनाए।

इसी प्रकार एशियन पेंट्स के लिए हर घर कुछ कहता है जैसा सांस्कृतिक कैम्पेन तैयार किया। जानें क्या दिख जाए स्लोगन के चार शब्दों वाले वाक्य ने राजस्थान की अनंत संभावनाओं, रहस्य, संस्कृति, कला, और प्राकृतिक सौंदर्य को एक पंक्ति में बाँध दिया। यह वाक्य हर किसी के मन में एक विज्ञासा जगाता था और रहस्य पैदा करता था। साथ ही पर्यटकों के भीतर राजस्थान यात्रा की इच्छा जगाता था। यह स्लोगन कहता था राजस्थान आइए, यहाँ हर कदम पर एक नया चमत्कार है। यह सैलानियों के मन में राजस्थान को रहस्यमय और आकर्षक भूमि दोनों रूपों में उभार देने वाली एक अनूठी अनुभूति थी। जानें क्या दिख जाए की खूबसूरती इसकी अनिश्चितता में छिपी थी। यह बताता है कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुँचना नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों का आनंद है। इस टेग लाइन के साथ चलाए गए टीवी विज्ञापनों और प्रिंट अभियानों में थार का मरुस्थल, ऊँट की सवारी, लोकगीत और नृत्य, किले–महल और राजस्थान के गाँवों की सादगी को दिखाया गया था। इस अभियान ने राजस्थान पर्यटन को नई ऊँचाई दी। साथ ही इससे देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। साथ ही राजस्थान की ब्रांड–इज़न सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसे संस्कृति, रंग और रोमांच के प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया।यह भारत के सबसे सफल राज्य–स्तरीय पर्यटन अभियानों में से एक माना गया।



स्व. पियूष पांडे

इस अभियान को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन अवाडर्स में भी सराहना मिली और पियूष पांडे की रचनात्मकता को इंडियन आइकॉन ऑफ एडवरटाइजिंग के रूप में स्थापित किया। पियूष पाण्डे की विज्ञापन–कला ने भारतीय उपभोक्ता–संस्कृति से गहरा संबंध बनाया तथा विज्ञापन को सिर्फ उत्पाद बेचने की कला से ऊपर उठकर कहानियों, भाषा–संवेदनाओं एवं स्थानीय भावनाओं से जोड़ा। उनकी इस शैली ने भारत के देशी विज्ञापन और दृश्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रतिष्ठित किया। भारतीय विज्ञापन जगत के इस महान क्रिएटिव जीनियस के जाने से भारतीय विज्ञापन–उद्योग ने एक दूरदर्शी क्रिएटर तथा संस्कृति–निर्माता खो दिया है। पियूष पांडे की जीवन यात्रा बताती है कि कैसे एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर, दृढ़ संकल्प, क्रिएटिव सोच और भारतीय संस्कृति के प्रति सच्चे निष्ठा से– विज्ञापन जगत में वैश्विक प्रभाव डाला जा सकता है। उनकी कहानियाँ– विज्ञापन सिर्फ बिक्की का माध्यम नहीं, बल्कि संवाद की कला थीं।

गोपेन्द्रनाथ भट्ट, साहित्यकार।

राजस्थान के सौर ऊर्जा का सिरमौर बनने में सवाई माधोपुर बना सहभागी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में कोलाड़ा एवं रामसिंहपुरा में 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित - 250 से अधिक कृषक परिवारों को सिंचाई के लिए दिन के समय सौर ऊर्जा आधारित बिजली मिलेगी



सुरेन्द्र कुमार मीणा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी ऊर्जा नीति और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सिरमौर राज्य बन चुका है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन ने नई ऊँचाइयों छू ली हैं, जिसमें सवाई माधोपुर जिला भी इस राष्ट्रीय ऊर्जा क्रांति का सशक्त सहभागी बन गया है। जिले के बौली उपखण्ड स्थित कोलाड़ा 33/11 केबी सब-स्टेशन क्षेत्र में हाल ही में 1.82 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह राज्य का 956वां सौर संयंत्र है, जिससे सवाई माधोपुर जिले की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राजस्थान ने पीएम–कुसुम योजना के कंपोनेंट–ए एवं कंपोनेंट–सी के अन्तर्गत अब तक 2,000 मेगावाट क्षमता से अधिक के विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर देश में एक नई मिसाल कायम की है। योजना के

कंपोनेंट–ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान तथा कंपोनेंट–सी में महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर पहुँच गया है।

इसी क्रम में सवाई माधोपुर सर्किल के रामसिंहपुरा 33/11 केबी सब-स्टेशन क्षेत्र में 1.12 मेगावाट क्षमता का विकेंद्रित सौर संयंत्र भी प्रारंभ किया गया है, कोलाड़ा एवं रामसिंहपुरा में 2.94 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से लगभग 250 से अधिक कृषक परिवारों को सिंचाई के लिए दिन के समय सौर ऊर्जा आधारित बिजली उपलब्ध होगी।

सवाई माधोपुर जिले में पीएम–कुसुम योजना के कंपोनेंट ए एवं सी दोनों घटकों में सराहनीय प्रगति हो रही है। सभी संयंत्रों की स्थापना उपरांत किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध हो सकेगी एवं कृषि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले में कुसुम योजना कंपोनेंट–ए के तहत अब तक कुल 3 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू हैं, जबकि अतिरिक्त 3.67 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों पर कार्य प्रगति पर है। जिले के सारसोपर में 1.42 मेगावाट एवं कोलाड़ा में 2.25 मेगावाट उत्पादन क्षमता के संयंत्रों का स्थापना अंतर्गत चरण में है।

किसानों के लिए लाभ का नया सूर्योदयप्रधानमंत्री कुसुम योजना ने देश भर में किसानों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। इस योजना से किसान अब बिजली व डीजल निर्भरता से मुक्त होकर सौर ऊर्जा का उपभोग



कर दिन के समय सिंचाई कर रहे हैं। इससे न केवल उत्पादन लागत में कमी आई है, बल्कि अतिरिक्त आय का मार्ग भी खुला है।

ऊर्जा विभाग एवं विद्युत वितरण निगमों द्वारा इस योजना को जमीनी स्तर तक सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।केंद्र सरकार ने राज्य की उत्कृष्ट प्रगति को देखते हुए कंपोनेंट–ए में वर्ष 2024–25 के लिए 397 मेगावाट और वर्ष 2025–26 के लिए 5000 मेगावाट क्षमता का अतिरिक्त आवंटन दिया है। वहीं कंपोनेंट–सी के लिए दोनों वर्षों में 2 लाख सोलर पंपों की अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गई है। अब तक केंद्र सरकार राजस्थान को कंपोनेंट–ए में 5500 मेगावाट तथा कंपोनेंट–सी में 4 लाख सोलर पंपों का

लक्ष्य आवंटित कर चुकी है।

कृषि एवं घरेलू विद्युत् कनेक्शनों को नई गति

राज्य सरकार ने कृषि कनेक्शन नीति–2017 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है कि पीएम–कुसुम योजना के तहत स्थापित सौर संयंत्रों से जुड़े फीडरों पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस निर्णय से सवाई माधोपुर जिले में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में जिले में 1,590 कृषि कनेक्शन लंबित हैं तथा 480 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। नई नीति के तहत इन आवेदनों के शीघ्र स्वीकृत होने से किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराना संभव होगा।

दीपावली से पूर्व बिजली कनेक्शन

जारी करने के लिए चलाया विशेष अभियान के दौरान 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मात्र 20 दिन में सवाई माधोपुर में 501 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए।

राजस्थान और सवाई माधोपुर जैसे जिले इस राष्ट्रीय उपलब्धि में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। जिले के कोलाड़ा, रामसिंहपुरा, बौली, मित्रपुरा और बोरखेड़ा जैसे क्षेत्रों में स्थापित विकेंद्रित सौर संयंत्र न केवल किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और ग्रामीण समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं।

–सुरेन्द्र कुमार मीणा, सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, सवाई माधोपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल के आग्रह पर राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से जोड़ा

अब इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को विशेष रूप से लागू करेगी केन्द्र व राज्य सरकार

कार्यालय संवाददाता
नई दिल्ली/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आग्रह पर केन्द्र सरकार ने तारबंदी कार्यक्रम में कई फसलों को शामिल किया है। साथ ही, राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से भी जोड़ लिया है। अब इन जिलों में 11 विभागों की 36 योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली यात्रा के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों नेताओं ने कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राजस्थान में सिंचाई हेतु टांकों की व्यवस्था को जारी रखने, 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने, योजना के अंतर्गत सांकेतिक आवंटन में वृद्धि करने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की उप-योजनाओं में तारबंदी कार्यक्रम को शामिल रखने तथा दलहन उप-योजना के अंतर्गत



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को नई दिल्ली यात्रा के दौरान केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात की थी।

कांटेदार तारबंदी पर अनुदान स्वीकृति जैसे कृषक हितैषी विषयों पर सार्थक निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा, किसानों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया। केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजस्थान के

विकास के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए जा रहे अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भजनलाल शर्मा, राजस्थान के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखकर

- **केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजस्थान के विकास के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की**
- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी शिष्टाचार भेंट कर राजस्थान के आर्थिक विकास, विभिन्न योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं जीएसटी बचत उत्सव पर चर्चा की**

टांका निर्माण पर रोक हटाने तथा विभिन्न योजनाओं में केन्द्रीय अनुदान बढ़ाने के लिए आग्रह किया था। केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए भजनलाल शर्मा ने केन्द्र सरकार की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी कई योजनाएँ लागू की हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने सोमवार को ही केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने राजस्थान के आर्थिक विकास,

विभिन्न योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं जीएसटी बचत उत्सव से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। शर्मा ने वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर वित्त मंत्रालय द्वारा जीएसटी दरों में की गई कमी का आम आदमी को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। इससे दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएँ सस्ती हुई हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव में हिस्सा लेते हुए आमजन ने त्यौहारों पर उत्साह के साथ स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी कर 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दिया है।

द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर न्याय मित्रों को दस्तावेज मुहैया कराएं

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट रजिस्ट्री को कहा है कि वह मामले में नियुक्त तीनों न्याय मित्रों को प्रकरण से जुड़ी डिजीटल पेपर बुक मुहैया कराए।

इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश पीएन मैदोला व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान अदालत की जानकारी में आया कि पूर्व में नियुक्त न्यायमित्र अलंकृता शर्मा, संशोधित तिवाडी और संदीप सिंह शेखावत को अदालत में रिपोर्ट पेश करनी है कि अदालती आदेश की पालना में राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की गई, लेकिन तीनों की न्यायमित्रों को अभी तक प्रकरण से जुड़े कागजात नहीं मिले हैं।

इस पर अदालत ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को कहा कि वे तीनों न्यायमित्रों को संबंधित दस्तावेजों

- **राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 3 दिसंबर को तय की है**

की पेपर बुक डिजिटल फॉर्मेट में मुहैया कराए। वहीं अदालत ने मामले की सुनवाई तीन दिसंबर को तय की है। न्यायमित्र अधिवक्ता अलंकृता शर्मा ने बताया कि अदालत ने 18 साल से विचारधीन इस प्रकरण से जुड़ी जमीनी हकीकत जानने के लिए गत सात अक्टूबर को तीन न्यायमित्र नियुक्त किए थे। उन्हें अदालती आदेश पर रिपोर्ट पेश करनी है कि अब तक मामले में राज्य सरकार की ओर से क्या कार्रवाई हुई, लेकिन पेपर बुक नहीं मिलने के अभाव में रिपोर्ट पेश नहीं की जा सकी। गौरतलब है कि पीएन मैदोला ने साल 2007 में जनहित याचिका दायर कर अमानोशाह नाला, जिसे अब द्रव्यवती नदी कहा जाता है, में अतिक्रमण को हटाने की गुहार कर रखी है। मामले के लंबित रहने के दौरान इसकी चौड़ाई तय करते हुए इसे पक्का किया गया है।

छठ महोत्सव : घाट सजेवली मनोहर,मईया तोरा भगती अपार...



उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वार्ड 5 स्थित सूर्य नगर, जेडीए कॉलोनी और गौतम विहार कॉलोनी में आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में शिरकत की।

जयपुर। सूर्य उपासना के चार दिवसीय छठ महोत्सव के तीसरे दिन सोमवार शाम को जयपुर में निवास कर रहे पूर्वांचल के श्रद्धालुओं ने सोमवार शाम अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर छठ ब्रतियों ने भगवान भास्कर की आराधना की। सोमवार रात्रि को भक्ति संगीत और छठ मैया के गुणगान के साथ जागरण का आयोजन हुआ। पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोक कलाकारों ने छठ मैया का स्थानीय भाषा में गुणगान किया। मुख्य आयोजन गीता जी तीर्थ में हुआ। यहां हजारों की संख्या में छठ ब्रती अर्घ्य देने पहुंचे। घाट सजेवली मनोहर,मईया तोरा भगती अपार, ।

लिहिए अरग है मईया, दिहीं आशीष हजार...लोग गीत के साथ 36 घंटे निर्जल निराहार रहे ब्रतियों ने अर्घ्य दिया। सोमवार को शाम ढलने से पूर्व ही गलताजी के घाटों पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ब्रतियों की भीड़ उमड़ी। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 5 स्थित सूर्य नगर, जेडीए कॉलोनी और गौतम विहार कॉलोनी में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का मध्य

- **अस्तगामी सूर्य को दिया पहला अर्घ्य, आज उगते सूर्य को देंगे दूसरा अर्घ्य**
- **दिया कुमारी ने छठ पूजा में शामिल होकर समुदाय के लोगों से बिहार चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की**

आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उपस्थित रहकर श्रद्धालुओं के साथ पूजा-अर्चना की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। दिया कुमारी ने कहा कि छठ पर्व हमारी सनातन संस्कृति, सूर्य उपासना, आस्था, अनुशासन और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का अद्भुत प्रतीक है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया है। मैं भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करती हूँ कि वे सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं प्रकाश का संचार करें। दिया कुमारी ने कहा कि, आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में मुझे जीत दिलाई थी, अब मैं चाहती हूँ कि बिहार चुनाव में भी एनडीए के प्रत्याशियों को वोट देकर सरकार बनाएँ। इस अवसर पर उदय शाह, उमेश गुप्ता, अवधेश

शाह, मंडल अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, मनदीप हुँजिल, श्रवण सिंह करीरी, राजू मीणा, सुनील कारोडिया, सुरेश मोर्य, सुरेंद्र सामेर, नेमीचंद सैन, मुकेश शर्मा, सविता गोयल, सुनीता राठौड़ सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बिहार समाज संगठन के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरेश पंडित ने बताया कि मंगलवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ महापर्व का समापन होगा। ब्रती लोग सूर्य के उदय होने से पूर्व ही बांस की टोकरी में नारियल, गन्ना, कच्ची हल्दी, नींबू, अदरक, सेव, संतरा सहित सभी तरह के मौसमी फल लेकर पानी में खड़े हो जाएंगे। जैसे ही सूर्य उदित होगा लोक गीतों के साथ परिवार की सुख-समृद्धि के लिए अर्घ्य प्रदान करेंगे।

सेंट्रल जेल में फिर मिले दो मोबाइल फोन

जयपुर। केंद्रीय कारागार में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। जेल प्रशासन ने कई बार औचक निरीक्षण किए ,ताकी की सलाखों के पीछे बैठे हाईकोर अपराधी किसी वारदात को अंजाम नहीं दे सकें। इसके बाद भी जेल परिसर में मोबाइल फोन मिलना अब आम बात होती नजर आ रही है। जेल प्रशासन ने रविवार को औचक निरीक्षण में बाथरूम और बैक से दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जिसके बाद जेल प्रशासन ने अज्ञात के खिलाफ लालकोठी थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सिम नंबर और मोबाइल फोन के ईएमआई नंबरों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। थानाधिकारी प्रकाश राम विश्‍नोई ने बताया कि जेल परिसर में मोबाइल फोन को लेकर आए दिन औचक निरीक्षण किया जा रहा है। रविवार शाम 7 बजे गश्त के दौरान वार्ड नंबर-7 के बाथरूम में एक मोबाइल लावारिस हालत में मिला।

ने बताया कि जेल परिसर में मोबाइल फोन को लेकर आए दिन औचक निरीक्षण किया जा रहा है। रविवार शाम 7 बजे गश्त के दौरान वार्ड नंबर-7 के बाथरूम में एक मोबाइल लावारिस हालत में मिला।

ज्योतिष-वास्तु सम्मेलन में जुटेंगे देश-विदेश के विद्वान

जयपुर। ज्योतिष शास्त्र में निहित तथ्यों को समसामयिक स्वरूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत करते हुए वास्तु शास्त्रीय परंपरा को प्रायोगिक दृष्टि से लोकोपयोगी बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय इंटरनेशनल एस्ट्रो वास्तु कॉन्फ्रेंस- 2025 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयोजित की जाएगी। अनेक जाने-माने ज्योतिष, वास्तु, वैदिक एवं टैरो रीडर विशेषज्ञ प्रतिभागियों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। देश-विदेश के लगभग 500 विद्वान भाग लेंगे। बाहर से आए हुए सभी विद्वानों के ठहरने की व्यवस्था आयोजन स्थल पर ही की जाएगी। सम्मेलन का शुभारंभ जयपुर

के आराध्य देव श्री गोविंद धाम में विराजित श्री गोविंद देव जी के मंगला दर्शन से होगा। प्रवेश केवल निर्मंजण के आधार पर ही प्रवेश होगा। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, श्री सरस निकुंज के अलबेली माधुरी शरण महाराज, कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय, विधायक बालमुकुंद आचार्य, रेणुका पुण्डरीक गोस्वामी, गोवत्स विठ्ठल महाराज, आचार्य शुभेष शरमन, जी.डी. वशिष्ठ, प्रो. डॉ. केदार शर्मा, प्रो. विनोद शास्त्री, डॉ. महेंद्र मिश्रा, अनिल कुमावत और हरमित चावला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। यह जानकारी ज्योतिषाचार्य डॉ. महेंद्र मिश्रा ने दी।

रेट में रोजाना कम से कम एक पीठ करेगी मामलों की सुनवाई

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट को कार्मिक सचिव ने आश्‍वस्त किया है कि सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण (रेट) की जयपुर बेंच में हर कार्य दिवस पर सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक कम से कम एक पीठ मुकदमों की सुनवाई करेगी। इसके साथ ही त्रत्येक बेंच में सुनवाई के लिए वीसी की सुविधा आरंभ की जाएगी। डीओपी सचिव के आस्‍वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने अधिकरण के रजिस्ट्रार को एक सप्ताह में पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा है। वहीं अदालत ने आगामी सुनवाई पर डीओपी सचिव को उपस्थिति से छूट देते हुए कहा कि वे इन बिंदुओं पर कामकाज की मांनिटरिंग करेंगी। जस्टिस अशोक

कुमार जैन की एकलपीठ ने यह आदेश सुमान कुमारी की याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान अदालती आदेश की पालना में डीओपी सचिव शुचि त्यागी और अधिकरण के रजिस्ट्रार राकेश मीणा अदालत में पेश हुए। डीओपी सचिव ने अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकरण की हर बेंच के लिए वीसी की सुविधा आरंभ की जाएगी। वहीं अधिकरण की वेबसाइट पर लाइव डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम के साथ-साथ अदालत कक्ष और भवन के बाहर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा, ताकि वकील दूरस्थ स्थान से भी अपने मामलों पर नजर रख सकें। इसके अलावा यदि आकस्मिक स्थिति में सभी बेंच बंद हो जाती है तो जोधपुर सहित

अन्य स्थान पर कार्यरत सक्रिंत बेंच वीसी के जरिए मामलों की सुनवाई करेगी और इसके लिए जयपुर पीठ से ऑनलाइन रिकॉर्ड भेजा जाएगा। याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में वकीलों ने अदालत को बताया था कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण का गठन किया है। जहां त्रत्येक मामले की सुनवाई के लिए दो सदस्यीय पीठ का गठन होता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से पीठ गठित नहीं होती या अंतिम समय पर रद्द हो जाती है। जिससे मामलों पर सुनवाई नहीं हो पाती। जबकि पूर्व में अधिकरण में वीसी स्थापित करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।

पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण एवं जड़ी-बूटियों की सतत खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन

जयपुर। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में मृदा स्वास्थ्य परीक्षण एवं जड़ी-बूटियों की सतत खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन 27 अक्टूबर से शुरू हुआ, जहां मंगलवार को भी जारी रहेगा। यह सम्मेलन केन्द्रीय आयुष मंत्रालय, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, आर्सीएससीएनआर-1 के तत्वावधान में होगा। कार्यशाला ऑटोमेटेड मृदा परीक्षण मशीन धरती का डॉक्टर (डीकेडी), के संदर्भ में स्वस्थ धरा और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने व वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई।

जहां पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण महाराज ने मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ, अमं वस्त्र और स्मृति चिह्नन भेंट करके किया। शुभारम्भ दीप प्रज्वलन, ध्वन्तरि वंदना और डॉ. अरुना तिवारी व अनंटा टीम के समूहगान से हुआ। स्वागत उद्घोषन, निदेशक मृदा भरुवा एग्री साइंस, डॉ. के.एन. शर्मा ने दिया। आचार्य और मुख्य अतिथियों ने सार पुस्तिका “स्वस्थ धरा और मेडिसिनल प्लांट्स: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फाइटोमेडिसिन्स एवं रिस्टोडेड इंडस्ट्रीज” का लोकार्पण भी किया। नाबार्ड के अध्यक्ष शाजी के.वी. ने मुख्य अतिथि के रूप में अपने संबोधन



में कहा कि नाबार्ड का प्रमुख उद्देश्य देश में स्थायी कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि, लघु उद्योग, कुटीर व हस्तशिल्प, यामोद्योग और अन्य ग्रामीण शिल्प के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। वर्तमान की आवश्यकता यह है कि ग्रामीण विकास में निवेश बढ़े और समावेशी तथा स्थायी कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। नाबार्ड देशभर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों का संचालन करते हुए कृषि प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि फसल की सुरक्षा से ही मानव

स्वास्थ्य की रक्षा संभव है। अब समय आ गया है जब हमें अपने पूर्वजों से पात मिट्टी को उसके मूल स्वरूप पुनः लौटाना चाहिए और मूल की भूल को सुधारना चाहिए। पतंजलि की डीकेडी मशीन मृदा संबंधी चुनौतियों को दूर कर धरती को रोगमुक्त बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसकी किट से केवल आधे घंटे में मिट्टी के आवश्यक पोषक तत्व: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, पीएच, ऑर्गेनिक कार्बन और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, का परीक्षण किया जा सकता है, जिससे मिट्टी में

- **पतंजलि और नाबार्ड मिलकर सृजनात्मक कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं : नाबार्ड अध्यक्ष शाजी के.वी**
- **सार्वभौमिक और निहित संपदा को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। श्रद्धेय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण**

पोषक तत्वों की कमी या अधिकता का सटीक पता चलता है। अपने व्याख्यान में मृदा भरुवा एग्री साइंस के निदेशक डॉ. के. एन. शर्मा ने बताया कि पतंजलि भरुवा एग्री साइंस ने जैविक खेती एक प्रणाली है जो रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के बजाय जैविक खाद, हरी खाद और फसल चक्र का उपयोग कर मिट्टी की उर्वरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्रदूषण मुक्त उत्पादन सुनिश्चित करती है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली फसल उत्पादन की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डीकेडी, ऑटोमेटेड मृदा परीक्षण मशीन बनाई है। इसके द्वारा मिट्टी से पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण तत्वों को रासायनिक तरीके से पृथक किया जाता है और उनके स्तर का मूल्यांकन किया जाता है। मृदा विश्लेषण पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा जानने का

एक प्रभावी तरीका है जो मृदा प्रबंधन, उत्पादन, लागत में कमी, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और उपज बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कृषि स्थिरता में सुधार होता है। कार्यक्रम में बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल ने पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित भूमि के बावजूद अतीकृत कृषि प्रणाली प्रभावी बताते हुए पारंपरिक ज्ञान, नवाचारी उपकरण और महिला प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, अन्य विशेषज्ञों प्रो बी. आर. कांबोज, डॉ. जे. एन. रैना, डॉ. जी.पी. राव और डॉ. प्रदीप शर्मा ने स्वस्थ मिट्टी, बेहतर फसल और प्रबंधन तकनीक से वैश्विक स्वास्थ्य के भविष्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। कार्यक्रम के अंत में पोस्टर सत्र के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अंत में सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।

संघीय ढांचे की समझ के बिना राजनीति कर रहे है तेजस्वी, यह बचकानापन : मदन राठौड़

जयपुर (कासं)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बिहार चुनाव, तेजस्वी यादव और राजस्थान में अंता उपचुनाव में विपक्ष के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। राठौड़ ने कहा कि तेजस्वी यादव अभी युवा हैं, उन्हें देश के संघीय ढांचे की समझ नहीं है। हमारा देश संघीय व्यवस्था से चलता है और जो निर्णय केंद्र सरकार लेती है, उसे हर राज्य को मानना होता है। कोई यह कह दे कि हम किसी केंद्रीय कानून को अपने प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे, यह न केवल बचकानी बात है बल्कि संविधान की अवमानना भी है। यह देश एक है और कोई भी प्रदेश इस देश से अलग नहीं है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी दोनों ही ऐसे बयान देकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं।

तेजस्वी की वही भाषा है जो पहले राहुल गांधी बोलते थे और अब तेजस्वी उसी शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता । बिहार में भाजपा की सरकार बनने वाली है और भाजपा की नीतियां हर राज्य में समान रूप से लागू होंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर कहा कि आज कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन अपने ही मुख्यमंत्री को किसने आज दिखाया? पार्टी किसने तोड़ी? नीचा जो 'हॉर्स ट्रेडिंग' की बातें कर रहे हैं, वही अपने नेताओं को बेचने पर मजबूर कर चुके हैं। क्या उनके अपने विधायक बिकाऊ माल हैं कि वे ऐसी

- **अंता चुनाव में कांग्रेस जैसा कलंकित उम्मीदवार भाजपा का नहीं, यहां भारी मतों से चुनाव जीतेगी भाजपा : प्रदेशाध्यक्ष**
- **कांग्रेस हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति, कभी किसी वर्ग विशेष के लिए तो कभी किसी गठबंधन के दबाव में है : मदन राठौड़**

आई है। कभी किसी वर्ग विशेष के लिए, कभी किसी गठबंधन के दबाव में। गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस को अपने साथियों की शर्तें माननी पड़ती हैं, वरना गठबंधन टूट जाता है। यही कारण है कि वह नैतिकता से समझौता कर रही है। राठौड़ ने कहा कि देश में यदि एसआईआर सर्वे या मतदाता सूची की समीक्षा हो रही है, तो यह स्वागत योग्य कदम है।

जिन लोगों ने गलत तरीके से अपने नाम जुड़वाए हैं, उन्हें ही दर लग रहा है। अगर कोई गलत नाम मतदान सूची से हटाया जा रहा है तो डरने की जरूरत क्यों ? देश का निर्णय देश का नागरिक करेगा। जो ईमानदार हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर कहा कि आज कांग्रेस एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन अपने ही मुख्यमंत्री को किसने आज दिखाया? पार्टी किसने तोड़ी? नीचा जो 'हॉर्स ट्रेडिंग' की बातें कर रहे हैं, वही अपने नेताओं को बेचने पर मजबूर कर चुके हैं। क्या उनके अपने विधायक बिकाऊ माल हैं कि वे ऐसी

बातें कर रहे हैं? राठौड़ ने कहा कि भाजपा ने न तो कोई विद्रोह है, न असंतोष। भाजपा पार्टी एकजुट है। चुनावी तैयारी पूरी है। हमारे उम्मीदवार मरोयाल सुमन और कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मैदान में जुटे हुए हैं। स्वयं वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी निगरानी कर रहे हैं। मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष कैसे भी गलत हथकंडे अपनाए, सफलता नहीं मिलेगी। हाल ही में करीबन 9 करोड़ रुपय और शराब जब्त की गई, ये गलत तरीके हैं, जो चुनावी नैतिकता के विरुद्ध हैं। जनता सब जानती है और समय पर जवाब देगी। राठौड़ ने कहा कि भजनलाल शर्मा की सरकार ने राजस्थान में जिस तरह तेजी से काम किया है, वह प्रशंसनीय है। पिछली कांग्रेस सरकार ने करीब साल में ईआसीपी और बिजली व्यवस्था पर कोई काम नहीं किया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रामजल सेतु परियोजनाएं शुरू हुई हैं, टेंडर जारी हुए हैं और पाइपलाइन का काम चालू हो गया।

